कराना राज्य सरकार के बस की बात नहीं रही है। मैं भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से जोरदार मांग करूंगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को आर्थिक रूप से ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रदान की जाए ताकि राज्य सरकार जो यह नष्ट हुई फसलें, वृक्ष और गरीब लोगों की भूमि, मकान, सड़कें इत्यादि जो भी खराब हुई हैं, उनकी पूर्ति कर सके।

(iii) ALLEGED EXPLOITATION OF LABOURERS ENGAGED IN STONE QUACIES AND CRUSHERS BY CONTRACTORS

श्री दौलत राम सारण (चुरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन खान मजदूर भयंकर शोषण के शिकार के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

मेवला महाराजपुर जिसे गधा-खोर भी कहते हैं, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ लकड़पुर, अनंगपुर, सराय कटन क्षेत्र की पत्थर की खानों और वहां लगे क्रेशरों पर दस हज़ार से भी अधिक खान मज़दूर काम करते हैं। इन खान मजदूरों का ठेकेदार बुरी तरह से शोषण कर रहे हैं।

ये खान मजदूर मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और ठेकेदारों द्वारा हरियाणा के हैं। इन हजारों मजदूरों को ठेकेदार द्वारा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। इनमें से अधिकांश स्थानीय भाषा हिन्दी नहीं समझते। इन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। आवास, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, शुद्ध पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात का इकट्ठा हुआ गन्दा पानी पीते हैं, जिससे गंदगी मलेरिया आदि से बीमार हैं। इन्हें सस्ते भाव पर अनाज आदि जीवनोपयोगी वस्तुएं देने की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

अन्तर्राज्यीय विस्थापित मज़दूर अधिनियम, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम आदि श्रमिकों के लाभ और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत इन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही कोई व्यवस्था है। इन हज़ारों मज़दूरों का भयंकर शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। ये मज़दूर केवल ठेकेदारों के रहम पर जी रहे हैं।

इन हज़ारों मजदूरों की चिन्ताजनक स्थिति से इनकी रक्षा की जाए। इनका शोषण उत्पीड़न समाप्त किया जाए। ये खानें, मजदूरों को सहकारी समितियां बना कर उन्हें पट्टे पर दी जायें, उन्हें ही क्रेशर लगवा कर दिए जायें और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके इनका शोषण समाप्त किया जाए।

आशा है सरकार का श्रम विभाग इस ओर ध्यान दे कर इन्हें राहत दिलाएगा।

(iv) ESTABLISHMENTS OF TWO MORE ATOMIC POWER UNITS TO SOLVE POWER CRISES IN RAJASTHAN

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चितौड़गढ़) : भारत में बिजली का संकट और अधिक बढ़ता जा रहा है इस से कृषि तथा लघु उद्योग बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। राजस्थान की स्थिति और भी अधिक दयनीय है। राष्ट्र के गौरव का प्रतीक राजस्थान परमाणु बिजली घर 8 वर्ष से लगातार बीमार चल रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच चार बिजली परियोजनाओं में साझेदारी है। गांधी सागर और सतपुड़ा से मध्य प्रदेश राजस्थान को बिजली नहीं दे रहा है। इधर रावतभाटा परमाणु बिजली घर का यह रिकार्ड है कि नियमित रूप से 8 दिन भी लगातार यह नहीं चला। बार-बार इसके बन्द होने से कृषि तथा उद्योगों को भारी क्षति हुई है।

हमें स्वदेशी ईंधन तथा भारी पानी का उपयोग इस में हो सके ऐसी व्यवस्था

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

करनी होगी। एक जांच कमेटी बनानी होगी तथा उन खराबियों को दूर करना होगा जिस से यह आठ दिन भी लगातार नहीं चल पाता।

थोरियम को यूरेनियम में बदलने के परीक्षण करने होंगे क्योंकि ऐसा अनुमान है कि दुनिया का 80 प्रतिशत थोरियम आक्साइड भारतीय खनिज सम्पदा है। अतः तारापुर परमाणु बिजली घर जो अमेरिकन ईंधन पर आधारित है, अब उस की निर्भरता कम हो जायगी। हमें तारापुर परमाणु बिजली घर को आत्मनिर्भर बनाना होगा।

अतः राजस्थान प्रान्त के पिछड़ेपन को देखते हुए विद्युत् की भारी कमी और कटौती को कम करने के लिए रावतमाटा में कार्यरत दो इकाइयों के स्थान पर दो और इकाइयां लगाई जा सकती है। पर शर्त यह हो कि ये इकाइयां पूर्णतः स्वदेशी हों।

इस के अतिरिक्त प्रान्त के पांचों संभागों में 5 थर्मल पावर प्लांट लगाये जाने चाहिए जिस से पिछड़ हुए राजस्थान के व्यक्ति हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति तथा भूरी क्रान्ति की ओर बढ़ सकें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Whatever you have given in writing only shall go on record, which has been approved by the Speaker.

(v) SEVERE DROUGHT SITUATION IN BHIL ATEAS OF DUNGANPUR DISTRICT OF RAJASTHAN

SHRI BHEEKHABHAI (Banswara) Under Rule 377, I am making a statement.

Drought in Rajasthan and other places in the country has been discussed in this House serval times during the earlier Sessions also. However, the situation in the Bhil areas of Dunganpur district has become so distressing that it is imperative on the part of the Central Government to immediately initiate some special schemes by way of relief measures to the lakhs of hunger-stricken people. These Bhils have their own way of living and have been traditionally keeping away from the onslought of modern civilization. They hardly have any improved ways of earning their livelihood. In nutshell they eat whatever they can manage daily. Total crop failure has fade their lives miserable.

(vi) RELIEF MEASURES FOR THE PEOPLE AFFECTEF BY HAIL STORM IN UTTAR PRADESH

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : गोरखपुर तथा उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में ओले पड़ने से जन-धन की भारी क्षति हुई है। अनेक लोगों की मृत्यु हुई है तथा करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो गई है। इस उपल-वृष्टि से लाखों कृषक परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं तथा प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिन परिवारों के लोग मरे हैं उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाय तथा जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उन का लगान माफ़ कर दिया जाय और उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाय। ओले से प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों की फीस माफ़ की जाय तथा जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाय। लोगों को इन सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना मानवीय दृष्टि से अतिआवश्यक एवं उचित है।